राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1257

26 जुलाई, 2017 को उत्तर के लिए

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड वितरक
योजना तथा आधुनिकीकरण कार्यक्रम

1257. श्री माजीद मेमनः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सेल (भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड) वितरक योजना के अंतर्गत विगत दो वर्षों में वितरकों (खुदरा बिक्री केन्द्र) की संख्या बढ़ गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य तथा जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड वर्ष 2016 में 2,50,000 टन तक की रेल की मांग को पूरा करने में विफल रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा अब तक विभिन्न आधुनिकीकरण कार्यों तथा विस्तार के लिए कितना संचयी व्यय किया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा 70,000 करोड़ रुपये के आधुनिकीकरण कार्यक्रम को पूरा करने के पश्चात् इस्पात की घरेलू मांग बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री विष्णु देव साय)**

(क): जी नहीं।

(ख): प्रारम्भ में, 2016-17 के लिये रेलवे बोर्ड ने बहुत बड़ी मात्रा में, 6,24,516 टन रेल्स आपूर्ति का मांगपत्र स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) को दिया था, जो सेल द्वारा पूरा किया गया और उसने 6,20,049 टन रेल्स की आपूर्ति 2016-17 के दौरान भारतीय रेल को की। हालांकि, वर्ष के दौरान 8,20,000 टन रेल्स की रेलवे द्वारा बढ़ाई गई आवश्यकता की आपूर्ति कम क्षमता के कारण नहीं की जा सकी। भारतीय रेलवे की 1.2 मिलियन टन की अतिरिक्त मांग की पूर्ति के लिए यूनिवर्सल रेल मिल, भिलाई इस्पात संयंत्र, सेल अब सक्षम है।

(ग): सेल द्वारा आधुनिकीकरण व विस्तार, खदानों और तत्संबंधी सस्टेनेंस स्कीम्स पर जून 2017 तक किये गए संचित व्यय की राशि रूपय 65,822 करोड़ है।

(घ): विनिर्माण और आधारी अवसंरचना पर ध्यान केन्द्रित करने के लिये सरकार ने 'मेक इन इंडिया' प्रारंभ किया है, जिसका उद्देश्य देश में मांग और आपूर्ति को बढ़ावा देना है। सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात नीति और 08.05.2017 को घरेलू लौह व इस्पात उत्पाद निर्माण (डीएमआई एंड एसपी) को सरकारी खरीद में प्राथमिकता देने की नीति को आधिसूचित भी किया है। ये नीतियां लौह एवं इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल माहौल उपलब्ध करवाती है।

*****